

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष : एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 22-पॉच/1993 - विरुद्ध आदेश दिनांक 12-01-1993  
पारित द्वारा - आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर - प्रकरण क्रमांक  
39/अ-56/1992-93 अपील

सरजू प्रसाद पुत्र दौलत चिड़ार

निवासी हडा बरोदा तहसील पाटन

जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री ए०के०अग्रवाल)

(शासकीय अभिभाषक श्री बी०एन०त्यागी)

आ दे श

(दिनांक 17 फरवरी, 2016 को पारित)

आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/अ-56/1992-93  
अपील में पारित आदेश दिनांक 12-1-93 के विरुद्ध यह निगरानी म०प्र० भू-राजस्व  
संहिता, 1959 की धारा-50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा वर्ष 1990 में जनगणना कार्य में  
सहयोग नहीं किया एवं शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती, जिसके आधार पर

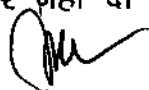




नायब तहसीलदार तहसील कटंगी ने आदेश दिनांक 31.10.90 से आवेदक को दण्डित कोटवार पद से प्रथक कर दिया । इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील होने पर आदेश दिनांक 17.01.91 से नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ । नायब तहसीलदार कटंगी ने प्रकरण क्रमांक 6 अ-56/89-90 में आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 5-6-1991 पारित किया तथा आवेदक को ग्राम के कोटवार पद से पृथक कर दिया । इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी पाटन के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 28 अ-56/90-91 में पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त 1991 से अपील निरस्त कर नायब तहसीलदार कटंगी के आदेश दिनांक 5-6-91 को स्थिर रखा गया । इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील क्रमांक 39/अ-56/1992-93 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 12 फरवरी 1993 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरुद्ध निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

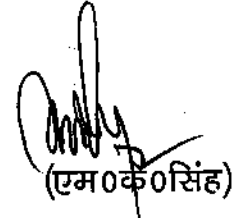
4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं नायब तहसीलदार कटंगी के आदेश दिनांक 5-6-1991 तथा अनुविभागीय अधिकारी पाटन के आदेश दिनांक 13-8-91 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि महेश प्रसाद नामदेव की ड्यूटी जनगणना कार्य में थी एवं जब वह आवेदक को कोटवार होने के नाते जनगणना कार्य में थी एवं जब वह आवेदक को कोटवार होने के नाते जनगणना कार्य में सहयोग के लिये बुलाने उसके घर गया तब आवेदक ने ड्यूटी पर आने से मना कर दिया । इसी प्रकार आवेदक ने नायब तहसीलदार के समक्ष बचाव में स्वीकार किया है कि उसने कोटवार के सेवा खाते की भूमि सिकमी पर दे दी थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि सेवा खाते की भूमि सिकमी पर नहीं दी जा सकती । हलका पटवारी ने भी कथन दिये



हैं कि आवेदक शासकीय कार्य संपादन में बहानेवाजी करके टालमटूल करता आया है जिसके कारण नायब तहसीलदार ने आवेदक को दो-दो बार बचाव प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का भी समुचित अवसर दिया है परन्तु आवेदक स्वयं के पक्ष में कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सका है जिसके कारण नायब तहसीलदार ने आवेदक को कोटवार पद से प्रथक किया है । वैसे भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/अ-56/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-1-93 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है ।

f  
Da



(एम०के०सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर